

देश की अपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03

अंक - 120

जौनपुर, गुरुवार, 19 दिसम्बर 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद 'आप' वृद्धजनों के निःशुल्क इलाज की योजना शुरू करेगी : केजरीवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली में उनकी पार्टी के सत्ता में लौटने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के निःशुल्क उपचार के लिए 'संजीवनी योजना' शुरू की जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में प्रस्तावित है। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के लिए पंजीकरण दो-तीन दिन में शुरू हो जायेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवी इस योजना के लिए पात्र बुजुर्गों का पंजीकरण कराने के लिए घर-घर जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद 'आप' सरकार इस योजना को लागू करेगी।

बंगाल सरकार गंगा सागर तीर्थयात्रियों के लिए पुल बनाने पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी : ममता

बंगाल, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार गंगासागर वार्षिक मेला आयोजन स्थल पर मुख्य भूमि को सागर द्वीप से जोड़ने वाली एक नदी पर पांच किलोमीटर लंबा पुल बनाएगी। बनर्जी ने कहा कि वे इस संबंध में उनकी बार-बार की गई अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार लेन वाले पुल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। बनर्जी ने प्रस्तावित पुल का नाम 'गंगासागर सेतु' रखा और कहा कि राज्य इसके निर्माण पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसकी निविदा जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा, "हमने केंद्र सरकार से बार-बार पुल के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए, हमने इसे खुद बनाने का फैसला किया है। अपेक्षित सर्वेक्षण किया गया और परियोजना के लिए डीपीआर तैयार निविदा पूरी हो गई।"

बीजेपी ने राजनैतिक फायदे के लिये संभल-बहाइच में कराई हिंसा : सपा

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनैतिक फायदे के लिए संभल की घटना कराई है। 17 दिसंबर को विधानसभा में अपने संबन्धित न नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सरकार से कहा कि प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में जाने से बचाइये। इससे आपसी भाईचारा टूटेगा। विधानसभा में सपा ने संभल व बहाइच की घटना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सपा सदस्य व संभल के विधायक इकबाल महमूद का नाम लेकर सीएम योगी ने बयान दिया था इस पर महमूद ने कहा कि उपचुनाव में वोट डालने नहीं दिया गया। 23 नवंबर को उपचुनाव का परिणाम आया, अगले ही दिन 24 नवंबर को फिर से सर्वे टीएम पहुंच गई। वहां जय श्रीराम के नारे लगाए गए। इससे वहां तनाव हो गया। मैं और मेरा बेटा वहां नहीं थे फिर भी हमारे नाम आ गए। भाजपा ने राजनैतिक फायदे के लिए यह घटना कराई। सपा विधायक ने मुख्यमंत्री योगी के बेटों को कट्टे के नारे को याद करते हुए कहा कि फिर आप हमें क्यों बांट रहे हो।

अयोध्या में मस्जिद बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ जमीन ली जाए वापस : सीएम योगी

अयोध्या, (संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित जमीन वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने दावा किया कि इस काम के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में उस स्थान पर मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था, जहां 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इसी आदेश में, शीर्ष अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ का



भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में जिले के धन्नीपुर क्षेत्र में सरकार द्वारा आवंटित पांच एकड़ भूमि पर एक नयी मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का गठन

उत्तर प्रदेश सरकार ने की 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति : संदीप सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति कर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा बदलने का कार्य किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं, सरकार खेलकूद और सर्वांगीण विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद परिषदीय विद्यालयों में व्यापक सुधार लाते हुए सरकार ने आधुनिक सुविधाओं और उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा का सपना

साकार करने की दिशा में तेजी से काम किया है। प्रदेश में विद्यालय बंद करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि, उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करके निजी स्कूलों के समकक्ष बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों की संख्या और विद्यालयों के विकास को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। इसके बाद

2020-21 में 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। 2023-24 में 12,460 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई। कुल मिलाकर सरकार ने अब तक 1,26,371 शिक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार इन मामलों की गंभीरता से पैरवी कर रही है और नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संजीदा है। भविष्य में जरूरत के अनुसार नई नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा। सरकार शिक्षा के साथ-साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। विद्यालय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और खेल उपकरणों के लिए

कि उनका "इरादा वहां मस्जिद बनाने का कभी नहीं था, बल्कि मस्जिद के बहाने कलह को कायम रखना था।" सिंह ने आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से, 'मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद निर्माण का इरादा कभी भी मस्जिद का निर्माण करना नहीं था, बल्कि मस्जिद की आड़ में अशांति और अव्यवस्था कायम रखना था, हालांकि, आपके नेतृत्व के कारण यह संभव नहीं हो पाया।" सिंह ने कहा, "वैसे भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की

आवश्यकता नहीं है।" सिंह ने "पीटीआई-भाषा" से कहा, "मुस्लिम समुदाय इस मस्जिद के माध्यम से केवल बाबर की विरासत को संरक्षित करना और बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहता है।" जब 'पीटीआई-भाषा' ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया के लिए अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन से संपर्क किया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सिंह ने 2022 में लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि ताजमहल भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और इसे 'तेजो महालय' के नाम से जाना जाता है।

एक साथ चुनाव संबन्धी जेपीसी में प्रियंका समेत चार कांग्रेस सांसद हो सकते हैं शामिल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार करने के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत चार सांसद शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी जेपीसी के लिए लोकसभा से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत तथा राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला का नाम भेज सकती है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024' और उससे जुड़े 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' को निचले सदन में पुररूस्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया। सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुररूस्थापित कर दिया गया। विधेयकपेश किए जाने के पक्ष में 263 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के उपरांत 'संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' को भी पेश किया।



देश में हिंदू-मुसलमान के अलावा भी बहुत कुछ, बेरोजगारी बड़ी समस्या : इमरान मसूद

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर धर्या। जिसको लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। संसद से सड़क तक चर्चा है। उच्च सदन में हुई बहस में उठाए गए मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राय रखी। उनके मुताबिक गैर जरूरी मसलों पर ज्यादा ध्यान दिया

राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, "हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। कांग्रेस 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, ये संविधान विरोधी है। वहीं यूसीसी को लेकर अमित शाह ने कहा कि, फ्म लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एक ऐसा कानून जिसे सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है, उसे उत्तराखंड ने आदर्श कानून के रूप में पारित किया।"

कैंग रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को कैंग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है कि कैंग (कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट को डेढ़ साल से दबा कर रखा गया। उन्होंने कहा, "रिपोर्ट के बारे में हमारी लगातार मांग है कि इसे हमारे एडवोकेट्स के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए और इसे सदन के पटल पर लाया जाए। सरकार इस रिपोर्ट को बार-बार दबाने की कोशिश कर रही है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। यह कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, और इसे असंविधानिक माना जा सकता है, क्योंकि यह संविधान के तहत लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है।" उन्होंने कहा, "हमने सरकार को स्पष्ट रूप से चुनौती दी है कि वह 48 घंटों



के भीतर इस रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पटल पर लाए। इसके लिए सदन की बैठक बुलाने की भी मांग की है।" उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी की सरकार इस रिपोर्ट को लेकर अपनी नीतियों से क्योंकि यह संविधान के तहत लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है।" उन्होंने कहा, "हमने सरकार को स्पष्ट रूप से चुनौती दी है कि वह 48 घंटों

जियाउर्रहमान बर्क ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, दायर की याचिका

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बुधवार को संभल हिंसा मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कि संभल हिंसा को लेकर सात एफआईआर दर्ज की गई हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पर संभल हिंसा भड़काने का आरोप है। एस्प्री कृष्णा बिश्नोई ने बताया था

कि संभल हिंसा मामले में अब तक 27,00 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज है। बर्क ने 29 नवंबर को आईएनएस से बातचीत में कहा था, "हम सर्वोच्च न्यायालय इसलिए गए थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इसाफ जरूर मिलेगा। कोर्ट ने अच्छा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पर संभल हिंसा भड़काने का आरोप है। एस्प्री कृष्णा बिश्नोई ने बताया था

गई है कि वह पूरे मामले में तटस्थ रहे।" सपा सांसद ने कहा था, "अब हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डालेंगे, जिसमें यह मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में आयोग गठित कर इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि प्रशासन द्वारा गठित आयोग से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।" 24 नवंबर को संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची टीम और पुलिसकर्मियों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा गया है। प्रशासन को हिदायत दी

मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर लगाया अंबेडकर का अपमान करने का आरोप, मांगा इस्तीफा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर विवाद बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने भाषण में डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। जिस पर अब राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुववार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "जब अमित शाह डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग 100 बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते, तो 7 बार स्वर्ग में जाते।"



इसका मतलब है कि बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना गुनाह है और इनका इरादा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का विरोध करना था। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। हालांकि बाबा साहेब अंबेडकर पर सदन की कार्यवाही चल रही थी, इसलिए

हम सभी ने खामोश रहने का फैसला किया। आज हम सभी पार्टी के नेताओं ने एक होकर इस पर सवाल उठाया। अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है वो गलत है। मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर पर सदन की कार्यवाही चल रही थी, इसलिए

कहा, "उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान का अपमान किया है। मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि वह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "शरद्विषय कैसे अमित शाह संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं।"

पिछले कुछ दशकों से भारत-चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे : राजीव रंजन

पटना, (एजेंसी)। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन दौरे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव रहा है। उन्होंने कहा, "दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में मतभेद रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी सीमावर्ती इलाकों में सीमा रेखा का निर्धारण शामिल है। उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, पिछले कुछ महीनों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला

है। सीमा पर जो तनाव और सैन्य टकराव की स्थिति बन गई थी, वह अब धीरे-धीरे घट रही है। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं की वापसी के लिए डोभाल के चीन दौरे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव रहा है। उन्होंने कहा, "दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में मतभेद रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी सीमावर्ती इलाकों में सीमा रेखा का निर्धारण शामिल है। उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, पिछले कुछ महीनों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला

प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और इसके परिणामस्वरूप भारत के बाजार की भूमिका बढ़ गई है। भारत का यह बाजार अब चीन के लिए भी एक महत्वपूर्ण और आकर्षक बन चुका है। इसके अलावा, व्यापारिक रिश्तों में सुधार से दोनों देशों के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलने की संभावना है।" उन्होंने कहा, "भारत और चीन दोनों ही राष्ट्र विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनके रिश्तों में सुधार से दोनों देशों को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी भारत और चीन के रिश्तों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत और चीन के बीच व्यापार का स्तर बहुत बढ़ा है। चीन भारत का एक

संपादकीय

विवाह में फायरिंग

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि विवाह आदि खुशी के मौके पर जानलेवा फायरिंग से मातम का माहौल बनने की तमाम घटनाओं के बावजूद इस बुराई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। विगत में ऐसी अनेक घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई और परिवारों के लिये जीवनभर का दुख छोड़ गए। इस बाबत कई बार अदालतों ने सख्त टिप्पणियां की और सामाजिक स्तर पर भी आवाजें उठी। लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात ही रहे। पिछले महीने पंजाब और हरियाणा में ऐसी ही तीन दर्दनाक घटनाएँ इस आत्मघाती लापरवाही से सामने आईं। जो इस घातक प्रथा के गंभीर परिणामों को ही उजागर करती हैं। ऐसी ही एक घटना में हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में एक बारात के दौरान तेरह साल की एक किशोरी की दर्दनाक मौत हर्ष फायरिंग में हो गई। साथ ही उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। ऐसे ही एक अन्य वाकये में फिरोजपुर में, एक दुल्हन तब गंभीर रूप से घायल हो गई, जब उसके भाई ने विदाई समारोह के दौरान लापरवाही से पिस्तौल चला दी। वहीं दूसरी ओर अमृतसर में ऐसी ही एक घटना सामने आई जब एक रिसॉर्ट में आयोजित विवाह समारोह में एक महिला हर्ष फायरिंग से घायल हो गई। निश्चित रूप से संवेदनहीनता से उपजी त्रासदियों को रोकने के लिये तत्काल कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है। यकीनी तौर पर इस कुप्रथा को रोकने के लिये जो गंभीर पहल समाज की ओर से होनी चाहिए, वह होती नजर नहीं आ रही है। इन हालात में एक आशा की किरण तब जगी जब सर्वजातीय अटगामा खाप ने जयन के दौरान होने वाली हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सामाजिक स्तर पर लिया। निश्चित रूप से खाप पंचायत का यह निर्णय स्वागत योग्य कदम ही कहा जाएगा। उसने चरखी दादरी की दुर्घटना में किशोरी की मौत के बाद यह प्रतिबंध लगाया है। निस्संदेह, खाप पंचायत की ओर से इस बुराई को दूर करने की यह कोशिश उसके सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को ही उजागर करती है। खाप ने फैसला लिया है कि ऐसी दुर्घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी जाएगी। उस व्यक्ति या परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी होगा। वक्त की नजाकत को समझते हुए लिया गया खाप का यह फैसला इस खतरनाक परिपाटी के खिलाफ शून्य सहिष्णुता को ही दर्शाता है। इस जानलेवा फायरिंग के खतरों को महसूस करते हुए जागरूकता अभियान चलाने का फैसला भी खाप की ओर से लिया गया, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ठोस पहल की जा सके। निस्संदेह, समाज में इस घातक दिखावे की सोच बदलने हेतु खाप की रचनात्मक पहल से शादियों व अन्य खुशी के अवसरों पर बंदूकों के दुरुपयोग की प्रवृति को खत्म किया जा सकेगा। उम्मीद करें कि पंजाब व हरियाणा में विभिन्न सामाजिक संगठनों को इस घातक प्रथा को समाप्त करने के खाप के सामूहिक संकल्प से प्रेरणा मिलेगी। बेहतर हो कि खाप की पहल का अनुपालन हो। हालांकि, सामाजिक स्तर पर यह जमीनी प्रयास महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम व हाईकोर्ट बार—बार जयन मनाने में गोलीबारी की अवैधता व खतरों की ओर ध्यान दिलाते रहते हैं। साथ ही इसे जीवन के प्रति लापरवाही से उपजा खतरा बताते रहते हैं। बल्कि यहां तक कि कौन ने ऐसे कृत्यों में गैर इरादतन हत्या की कोशिश को रूप में कार्रवाई किये जाने की भी बात कही है। वहीं दूसरी ओर बंदूक से जुड़े नियमों को भी सख्ती से लागू करने की जरूरत है। साथ ही कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरक्त बंदूक लाइसेंसिंग मानदंडों के अतिक्रमण के मामलों को रोकने के लिये सुरक्षा प्रोटोकॉल की शिक्षा दी जानी अनिवार्य की जानी चाहिए। लोगों को जागरूक होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उत्सव में हर्ष फायरिंग जैसी त्रासदियों की छाया से मुक्त होकर खुशियों के पल बरकरार रहें।

चट मंगनी पट तलाक से हलकान जिंदगी

राकेश
उसके सिर पर बड़ा—सा व्हाइट—क्रॉस चिपका हुआ था। मैंने छेड़ा, ‘भाभी जी से झगड़कर आए हो?’ वह चौंका, ‘तुम्हें कैसे मालूम?’ मैं समझा मजाक कर रहा है। दिलो—दिमाग में उसकी सुखी वैवाहिक जीवन की छवि बनी हुई थी। उसने खुद बताया था कि उनकी आपसी समझ कितनी अच्छी है। मैं उनकी ‘अंडर—स्टैंडिंग’ से प्रभावित था—बीवी हो तो ऐसी। तभी वह उदास—सा बोला, ‘नहीं यार, तेरी भाभी ने सिर पर फूल मार दिया।’ मैं चौंका, ‘अरे! फूल से ऐसी चोट लगती है भला?’ वह रुआंसा होकर बोला, ‘दरअसल, फूल गमले में लगा था और गुस्से में गमला सहित सिर पर दे मारा।’ एक सुखी विवाहित का ऐसा रूप! जब उसकी शादी न हुई थी तब वह मर—मिटने को तैयार था, कहता था— यदि उससे शादी न हुई तो मर जाएगा। अब मर रहा है तो रोता है? यह घटना चुटकुले—सी लगती है। वास्तव में सच्चाई से चुटकुले जनमते हैं। जिसे लोग समाज, राजनीति, व्यवस्था या धर्म के डर से सीधे नहीं सुन पाते, उसे चुटकुला कहकर स्वीकारते हैं। चुटकुले सच्चाई को बेअसर कर देते हैं। आपसी अंडर—स्टैंडिंग का जामा पहने पति—पत्नी घर के बाहर अच्छे लगते हैं। अच्छी पोशाकें, कॉस्मेटिक्स व परफ्यूम का जादू हटते ही सब कुछ बदल जाता है। कुंठाएं, अनबन, तनाव, तू—तू, मैं—मैं, मारपीट और प्रताड़नाएं नष्ट करने लगती हैं। विवाहित जीवन की मधुरता दूसरा खूबसूरत पहलू भी है। खबर है एक विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी तो उसके दुखी पति ने इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। अनोखी है विवाहित जीवन की ऐसी लालसा। प्यार के चरमोत्कर्ष का ऐसा अनूठा रूप है। हालांकि, मसखरे कहते हैं— बगैर शादी मुक्ति नहीं मिलती। शादी पूरे स्वर्ग से उतरी अप्सरा—सी वधू पति के घर को स्वर्ग बनाती है तथा पति को स्वर्गवासी! बहरहाल, आज मैं कुंवारे दिनों को याद करता हूं तो नाक से ‘घर—घर जल’ के नलों की तरह सूं—सूं कर हवा निकलती है। मन के नल से आंसुओं की सप्लाई नहीं होती। हमें याद है, हमारी शादी ‘चट मंगनी पट ब्याह’ के दौर में हुई थी। हमने लड़की देखी और हां कर दी। चट मंगनी हो गई। पंडित ने 27 गुणों का मिलान करके पट ब्याह करा दिया। बस, यहीं गड़बड़ी हो गई। पंडित की गुण—मिलान—एय्यूरीसी ने कठिनाई पैदा कर दी। मेरी प्रत्येक पसंद न—पसंद पत्नी की पसंद न—पसंद से बिल्कुल मिलती है। मुझे खाना—बनाना पसंद नहीं, उसे भी नहीं। मुझे आराम अच्छा लगता है, वह भी आराम—परस्त है। बहरहाल, अब पछताने से क्या होगा? पत्नियां नाराज न हों। उनका दोष नहीं है। विवाहित जीवन के सवालों का कोई अचूक जवाब नहीं होता। कुछ दिनों से पश्चिमी सभ्यता ने नई सोच दी है— चट शादी, पट तलाक।

विचार

आर्थिक रोडमैप के साथ दिल्ली से लौटे दिसानायक

पुष्परंजन
सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेड दिसानायक ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत को चुना। इससे हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा आएगी।’ मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका बिजली ग्रिड संपर्क और बटु—उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। दिसानायक के की पार्टी, ‘नेशनल पीपुल्स पावर’ (एनपीपी) की मार्क्सवादी विचारधारा में जड़ें होने के कारण नई दिल्ली में कुछ चिंताएं पैदा हुई थीं, कि उनका झुकाव चीन और होगा। लेकिन, कोलंबो में ‘सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स’ के कार्यकारी निदेशक पैकियासोथी सरवनमुद्दू के अनुसार, ‘नई दिल्ली को अपना पहला विदेशी पड़ोस बनाकर उन्होंने संकेत दिया, कि भारत वास्तव में हमारा सबसे करीबी सहयोगी होगा। यह इस यात्रा का प्रतीकात्मक आयाम है।’ सबसे दिलचस्प यह है कि दिसानायक की रविवार से आरम्भ तीन दिवसीय भारत यात्रा पर चीन से अधिक, अमेरिका की नजर रही है। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक की दिल्ली यात्रा से दस दिन पहले, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक मंत्री डोनाल्ड लू, अमेरिकी वित्त विभाग में एशिया—प्रशांत के

व्यावहारिक नीतियों से ही हासिल होंगे लक्ष्य

डॉ. यश गोयल
राजस्थान की भाजपा सरकार ने 2023—28 के लिए दस प्रमुख संकल्पों पर आधारित कार्ययोजनाएं बनाई हैं। इनमें प्रमुख रूप से—अमेरिका की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डालर बनाने, बुनियादी सुविधाओं का विकास, सुनिर्ोजित क्षेत्रीय विकास, किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण, बड़े उद्योगों और एमएसएमई को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण, मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, गरीब और वंचित परिवारों के लिए गरिमायम जीवन सुनिश्चित करना और पारदर्शी प्रशासन के लिए ‘परफॉर्म, रिफॉर्म एण्ड ट्रांसफॉर्म’ का सिद्धांत लागू करना शामिल है। गत दिनों भजनलाल सरकार की ‘राइजिंग राजस्थान इकोनोमिक समिट’ में लगभग 32 देशों के आर्थिक विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 35 लाख

आरोप—प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा संविधान पर चर्चा का सत्र

ललित
सर्वाच्च लोकतांत्रिक सदन लोकसभा संजीदा बहस की जगह हंगामे का केंद्र बनती जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है। जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बहस की जगह शोर शराबा, हंगामा और सदन का खण्टिगत होना ही आम होता जा रहा है। यही बात लोकसभा में संविधान को लेकर हुई दो दिनों की बहस की चर्चा के दौरान देखने को मिली। संविधान निर्माण के 75वें वर्ष पर हुई यह चर्चा भी छिछालेदार, आरोप—प्रत्यारोप एवं उच्छृंखलता का माध्यम बनी, जबकि संविधान पर इस चर्चा से जनता को एवं देश को सही दिशा मिलनी चाहिए थी, संविधा ण के प्रति प्रतिबद्धता दोहरायी जानी चाहिए थी। संविधान जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक बहस न होना लोकतंत्र को कमजोर करने एवं लोकतंत्र रूपी उजालों पर कालिख पोतना ही है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक—दूसरे को कठघरे में खड़ा करने का काम करके आकाश पर पैबंद लगाने एवं सखिद्र नाव पर सवार होकर संविधान रूपी सागर की यात्रा करने का ही संकेत देकर देश की जनता को निराश ही किया है। भले ही अपने तर्कों एवं तथ्यों से पक्ष एवं विपक्ष ने अतीत के प्रसंगों और विषयों को अधिक रेखांकित किया गया हो। निश्चित ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग—अलग नजरियों को स्पष्ट करने वाली यह बहस न केवल समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि लोकतंत्र, समाज और इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को

भारत को हमारा समर्थन और सहयोग निरंतर मिलेगा।’ सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स के कार्यकारी निदेशक सरवनमुद्दू के अनुसार, ‘श्रीलंका को भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना है, लेकिन दिसानायकें बहुत व्यावहारिक हैं। वे कष्टर वामपंथियों की तरह विचारक नहीं हैं। वह जानते हैं कि भारत उसका सबसे करीबी और मुसीबत में मददगार पड़ोसी है। चीन भी श्रीलंका में होगा।’ लेकिन इस सवाल पर कि क्या चीन को बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी? सरवनमुद्दू बोलते हैं, ‘मुझे नहीं लगता, कि ऐसा जरूरी होगा।’ राष्ट्रपति अनुरा दिसानायकें की यात्रा से पहले, कोलंबो की ओर से स्पष्ट किया गया कि अडानी समूह द्वारा विकसित किए जा रहे बंदरगाह परियोजना को हमें आगे बढ़ाना है। इससे पहले दिसानायकें के कार्यालय ने कहा था, कि हम अडानी परियोजना की समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमसे यह छिपाया था कि भारत में एक विशाल सौर ऊर्जा परियोजना को कथित तौर पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्तव योजना के तहत सुविधा प्रदान की जा रही थी। बहरहाल, ‘अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड’ के शेरय मंगलवार सुबह से चर्चा में हैं। क्योंकि, अडानी समूह की इस कंपनी ने कहा है कि वह अमेरिकी फंडिंग की मांग नहीं करेगी। इसके

पारदर्शी माहौल है। सरकार ने नौ नई पॉलिसियों के माध्यम से निवेशकों को विश्वास दिलाया है कि एमएसएमई, कलस्टर डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, एक जिला एक उत्पाद, निर्यात प्रोत्साहन, पर्यटन, खनिज, एम—सैंड और एवीजीसी एक्सआर जैसे क्षेत्रों में व्यापार में कोई रुकावट नहीं आएगी। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भीलवाड़ा में मक्का हब, बाड़मेर में इसबगोल और झालावाड़ में सोयाबीन अग्रणी उत्पाद बनने की संभावना है, यदि सही निवेश आता है। राजस्थान देश में सरसों की 50 प्रतिशत पैदावार करता है और टॉक जिला सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपये का तेल निर्यात करता है। अगर केंद्र और राज्य सरकार सरसों पर लगने वाला टैक्स हटा दें, तो उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर खाद्य तेल मिल सकता है। इसके साथ ही, प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों

बजाय, श्रीलंकाई बंदरगाह परियोजना के लिए अपने संसाध्ानों का इस्तेमाल करेगी। अडानी पोर्ट्स ने कहा कि श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) परियोजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, और अगले साल की शुरुआत तक चालू होने की राह पर है। अडानी पोर्ट्स ने कहा, ‘हमने डीएफसी से वित्तपोषण के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है।’ अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के एमडी और सीओओ अनिल सरदाना ने बताया, ‘श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों मन्नार और पूनरी में 500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना प्रगति पर है।’

मंगलवार को श्रीलंकाई कैबिनेट द्वारा जारी बयान में कहा गया, ‘अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी को फरवरी, 2023 में 442 मिलियन डॉलर निवेश करने, और मन्नार शहर और पूनरी गांव में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की मंजूरी मिली थी, जो दोनों श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित हैं।’ अडानी समूह कोलंबो में श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर 700 मिलियन डॉलर की टर्मिनल परियोजना के निर्माण में भी शामिल है। सितंबर 2021 में शुरू की गई ‘सीडब्ल्यूआईटी’ परियोजना, श्रीलंका के बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी



निवेश है। 35 साल के समझौते की कीमत 1 बिलियन डॉलर है। यह टर्मिनल श्रीलंका की सबसे बड़ी और सबसे गहरी कंटेनर सुविधा वाली होगी, जो अल्टा लाज कंटेनर वेसल्स का संचालन में सक्षम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अडानी पोर्ट्स के पास श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और जॉन कील्स होल्डिंग्स के साथ साझा उद्यम में 51 फीसद हिस्सेदारी है। यह परियोजना 2025 की शुरुआत में चालू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी के अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ राष्ट्रपति दिसानायकें की बैठक सोहार्दपूर्ण माहौल में हुई। डॉ. जयशंकर ने पर्यटन, निवेश और ऊर्जा क्षेत्रों में श्रीलंका का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चर्चा में मत्स्य उद्योग को आगे बढ़ाना, समुद्र सीमा उल्लंघन करने वाले मछुआरों को कैसे अलर्ट करना

आरोप—प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा संविधान पर चर्चा का सत्र

के कारोबार में परेशानी नहीं आए इसलिये राज्य सरकार ने एक ‘प्रवासी विभाग’ (मंत्रालय स्तर का) गठन की भी घोषणा की। हालांकि, बहुत तेज मार्ग की दूरी अधिक है। पूर्वी राजस्थान में जयपुर, अलवर और एनसीआर में पहले से ही निवेश हो चुका है, क्योंकि वहां रीको का नीमराना और हरियाणा सीमा पर अच्छा प्रभुत्व है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में सोलर ऊर्जा का इतना विस्तार हो चुका है कि वहां गोडवन और पक्षियों का जीवन खतरों में है। खनन और खनिज सेक्टर (बीकानेर, सिरोही, जालौर, जोधपुर और कोटा) में और अधिक संभावनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की बार—बार की रोक के कारण संकट बना रहता है। राज्य के बड़े शहरों के बीच एयर कनेक्टिविटी बहुत कम उपलब्ध है, जो विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ी अड़चन है। पर्यटन स्थलों पर अव्यवस्थित

आरोप—प्रत्यारोप की भेंट चढ़ा संविधान पर चर्चा का सत्र

निरुद्देश्यता एवं स्तरहीनता को ही दर्शाने वाला कहा जा सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह भी बताना चाहिए कि संविधान पर बहस करते समय सावरकर का नाम लेना और मनुस्मृति दिखाना क्यों आवश्यक हो गया था? कांग्रेस



को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी के उल्लेख करते रहने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू—तू मैं—मैं चलती रहती है, लेकिन इसमें महापुरुषों को घसीटना अब बंद होना चाहिए। हमारे हर महापुरुष ने अपने समय, समाज और समझ की सीमाओं में रहते हुए कुछ ऐसा योगदान किया, जिसके लिए हम कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसका मतलब उनके हर विचार से सहमति रखना या उनके हर कृत्य को समर्थन देना नहीं है। लेकिन उनके प्रति समाज की या उसके एक हिस्से की भी भावनाओं का सम्मान हमारी राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी का

उन्होंने कहा कि संविधान पार्टी विशेष नहीं बल्कि राष्ट्र का है, पार्टी विशेष ने संविधान निर्माण को हाईजैक कर लिया। निश्चित ही संविधान देश का सुरक्षा कवच है। लोकसभा में संविधान पर बहस की मूल आवश्यकता उन कारणों पर बुनियादी चर्चा की थी जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी भी अधूरे हैं और नियम—कानूनों पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, इसमें शक नहीं कि भाजपा का केंद्र यही सवाल रहा कि कौन संविधान और संवैधानिक मूल्यों को लेकर समर्पित है और कौन इस पर दोहरा खेल खेल रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सावरकर के सहारे भाजपा पर निशाना साधा वहीं प्रध्ानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रध्ानमंत्री पंडित नेहरू की गलतियां गिनाईं। कांग्रेस सांसद प्रियका गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने संविधान के रूप में मिले सुरक्षा कवच को तोड़ा है। भारत का संविधान, संघ का विधान नहीं है। इसी बात को दोहराते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है, जबकि वास्तविकता यह है कि संविधान के निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका रही है जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था, वह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह जनआकांक्षाओं का प्रतिबिंब था।

